ISSN 2348-3857

21वीं सदी में भारत-चीन सम्बन्ध: सम्भावनाएँ

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

डॉ. राजेश कुमार शर्मा

निदेशक, नेहरू अध्ययन केन्द्र, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

रामसिंह नाथावत

व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालसोट, दौसा (राजस्थान)

शोध सारांश

इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन और भारत दोनों आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती दो अर्थव्यवस्थायें हैं और यहाँ की बड़ी आबादी एवं बाजार सम्पूर्ण विश्व की आशाओं का (आर्थिक) केन्द्र है। सम्पूर्ण विश्व आज भी आर्थिक मंदी से उबरने का रास्ता भारत एवं चीन जैसे देशों में ही ढूँढ़ते हैं एवं इन देशों में ही सुरक्षित निवेश के लिये दौड़ में शामिल हैं। इस दौड़ का लाभ भारत और चीन दोनों उठाना चाहते हैं इसलिये दोनों में प्रतिस्पर्धा होना भी लाजमी है लेकिन एक अन्य तत्व सहकार या सहयोग का है यदि इसे बलवती बनाया जाता है तो यह उक्ति सफल हो पायेगी की 21वीं सदी एशिया की सदी होगी आज वह समय आ गया है।आज दोनों देश अपने विवादित मुद्दों को यथावत रखते हुए भी परस्पर लाभ हेतु अधिक और अधिक व्यापार-वाणिज्य को बढ़ावा दे रहें हैं। वैश्विक मंच पर आतंकवाद, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे अनेकानेक मुद्दों को साझा भाव से उठा रहे हैं। एशिया में किसी भी पश्चिमी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप दोनों को ही बर्दाश्त नहीं हैं। दोनों मिलकर अपनी सामर्थ्य को बढ़ा रहे हैं। 1962 में प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध की विभीषिका को झेलकर भी निरंतर दोस्ताना माहौल के सृजन और सम्बन्धों को नित नवीन ऊँचाईयाँ देने में लगे हैं। अत: यह देखा जाना दिलचस्प रहेगा कि भविष्य में दोनों देशों के सम्बन्ध कैसे रहेंगे? हाँलाकि भविष्य के गर्त में क्या छुपा है यह जानना काफी मुश्किल है लेकिन जिस प्रकार के ऐतिहासिक सम्बन्ध दोनों देशों के रहे हैं और आज उनकी दशा और दिशा कैसी है यह जानने के बाद कुछ-कुछ अंदाजा इनके भविष्य की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में लगाया जा सकता है।

संकेताक्षर : *ऐतिहासिक सम्बन्ध, आर्थिक-व्यापारिक सहकार, व्यापार सन्तुलन, पारस्परिक सहयोग*

भारत-चीन सम्बन्धों में भविष्य की संभावनाओं में यदि सहकार के बिन्दु रेखांकित किये जाये तो उनमें आपसी व्यापार-वाणिज्य, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, प्रतिरक्षा, आदान-प्रदान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, आतंकवाद से मुकाबला, एशिया को वैश्विक क्षितिज में सर्वोच्चता पर लाना आदि को प्रमुखता से लिया जा सकता है। साथ ही पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर के क्षेत्र में सहयोग, विश्व व्यापार संगठन एवं विश्व बैंक में हितों को प्रमुखता से एक होकर रखना, जलवायु परिवर्तन, एशिया में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने और विकसित देशों के प्रभुत्व को रोकने के क्षेत्र में साझा भाव से काम करना दोनों के लिये आज के वैश्विक परिदृश्य की आवश्यकता बन गया है।[1] दोनों के सहयोग के उक्त बिन्दुओं पर चर्चा से पूर्व हमें यह तो याद रखना चाहिए कि दोनों देश एक-दूसरे की क्षमताओं को अपने-अपने लाभ के लिये पूर्ण दोहन कर सकते हैं साथ ही एक दूसरे की अच्छाइयों-बुराईयों से सीख लेकर भी आगे सावधानी से कदम बढ़ा सकते हैं।

आज चीन की अर्थव्यवस्था 9 ट्रिलियन डॉलर की है जबकि भारत की 2 ट्रिलियन डॉलर। देखते ही देखते शंघाई दुनिया के सबसे वैभवशाली समृद्ध शहरों में गिना जाने लगा। चीन ने 1981 से 2013 के बीच 68 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जो मानव इतिहास में एक कीर्तिमान है जबकि भारत की स्थिति उतनी ज्यादा सुखद नहीं है। आखिर कैसे चीन ने इतनी लंबी और उँची छलांग लगाई? भारत इस उदाहरण से काफी कुछ सीख सकता है।चीन में धंधे का एक फार्मूला है। वे कोई भी सौदा छौड़ते नहीं है और किसी भी सौदे में नुकसान नहीं उठाते। वे हर मूल्य का माल बनाते है। अच्छा भी और सस्ता व घटिया भी।[2] यही वजह है कि 2011 में 40 हजार भारतीय व्यापारी यहाँ पहुँचे जबकि 2015 में तीन लाख 60 हजार। केवल भारत ही नहीं दुनिया भर के व्यापारी यहाँ पहुँच रहे है। भारत से यहां आने वाले व्यापारियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक पूरी सड़क भारतीय रेस्टोरेन्ट और

होटलों से भरी हुई है। चीन ने पहले कारखाने बनाए फिर उत्पाद को बेचने की यह व्यवस्था की। अब निर्यातकों को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है और कारखाना मालिकों को भी खरीददार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है।

1980 में जब चीन ने आर्थिक बदलाव शुरू किये तब वहाँ साक्षरता करीब 65 फीसदी थी इतना ही नहीं पढ़े लिखे होने के साथ-साथ काम में चीन की महिलाओं की भागीदारी 74 प्रतिशत है जबकि भारत में यह 34 प्रतिशत है। निवेशकों के लिये यहाँ इससे भी बड़ी बात यह थी कि यहाँ न तो हड़ताल होती थी न यूनियन बाजी न ही अपनी इकाई लगाने से पहले अफसरों से अनुमति के लिये भ्रष्टाचार का सामना होता था।

दोनों देशों के बीच 21वीं सदी में सम्भावनाओं को तलाशने के प्रयास में हमें सबसे पहले ध्यान आर्थिक-व्यापारिक सहकार की ओर लगाना होगा क्योंकि आज समय अर्थ का है, आज का युग आर्थिक समृद्धि का युग है सैनिक तानाशाही का नहीं। भारत-चीन दोनों के सम्बन्धों में सबसे अधिक सम्भावनाओं का क्षेत्र आपसी व्यापार कर एक दूसरे की विकास की गति को बढ़ाने का है। ऐसा करना अब एक दूसरे की जरूरत बन गया है यदि विकास की राह पर सरपट दौड़ना है तो। क्योंकि आज भारत को चीन से निवेश की उम्मीद है तो चीन को तेजी से बढ़ता भारतीय बाजार चाहिए। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच व्यापार 2015 तक 100 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को छूने जा रहा है।[3] शायद यह व्यापार जनित आत्मविश्वास, अविश्वास को दूर करेगा और सम्बन्धों में स्थिरता लायेगा जिससे अन्य समस्याओं के भी समाधान निकाले जा सकेंगे।

21वीं सदी में भारत-चीन के सम्बन्ध किस प्रकार के होंगे इस बात को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला निर्णायक तत्व दोनों का आपसी आर्थिक सम्बन्ध और व्यापार होगा। यही वजह है कि दोनों देश आज तेजी से एक दूसरे से आर्थिक व्यापारिक सम्बन्धों में बढ़ोतरी करने में लगे हैं। मई 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के कारोबारियों के बीच 1.40 लाख करोड़ के समझौते सम्पन्न किये गये है। भारतीय बैंक आई. सी.आई.सी.आई. ने अपनी शाखा चीन में खोली है। एयरटेल के साथ चाइना डवलपमेंट बैंक ने दो अरब डॉलर और इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने 50 करोड़ डॉलर कर्ज का समझौता किया है। इस प्रकार अब एक दूसरे देश के व्यापार कारोबारी अब प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने लगे हैं।

एसोचैम ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन की आर्थिक स्थिति का भारत के कारोबार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। चीन की अर्थव्यवस्था बिगड़ने से भारत को नफा कम और नुकसान ज्यादा होता है। यह एक तथ्य है कि भारत और चीन दोनों ही इस समय वैश्विक निवेशकों के आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं ऐसे में चीन के बाजारों के गिरने या वहाँ आर्थिक मंदी के दौर मात्र से भारत में निवेश नहीं होगा क्योंकि जब तक विदेशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती नहीं दिखाई पडेग़ी वे वहाँ पैसा नहीं लगायेंगे। उद्योग संगठन एसोचैम ने आज यहाँ जारी एक रिपोर्ट में कहा कि चीन में माँग की कमी से भारत में भी प्राथमिक उत्पादों की कीमतें कम होगी लेकिन धातु एवं खनन क्षेत्र पर निर्भर भारतीय कम्पनियों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा, विशेषकर भारतीय इस्पात प्राधिकरण, टाटा स्टील और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जैसी कंपनियों को। उस पर भी भारतीय कंपनियाँ कर्ज में डूबी हुई है उन पर ऊँची ब्याज दर और सुस्त मांग की मार भी है तथा लाभ का अंतर कम होने से वे दबाव में भी है।[4]

डॉ. अलका आचार्य (डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज, दिल्ली) का कहना है कि कारोबार के मामले में अब भारत-चीन दोनों एक नया फलक रचने को तैयार है। दोनों देश आज अपने विवादित मुद्दों को इन नये कारोबारी रिश्तों पर हावी नहीं होने देना चाहते है। दोनों तरफ ऐसा भरोसा भी दिख रहा है यही वजह है कि मोदी द्वारा मई 2015 में चीन की यात्रा के दौरान 24 समझौते सम्पन्न हो पाये जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। नतीजतन शंघाई में इंडिया-चाइना बिजनेस फोरम में 20 बिलियन डॉलर कारोबारी समझौते की आशायें इस यात्रा के दौरान बनी यह ध्यान देने योग्य बाते है कि दो देशों के बीच के आर्थिक समझौते अमूमन कई मुद्दे पाट देते है। अगर दोनों देशों को दुनिया में अपनी आवाज बुलंद रखनी है तो हमें एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरना होगा। इस अर्थ में चीन और भारत के बीच मजबूत आर्थिक सम्बन्ध जरूरी है।

व्यापार संतुलन की दिशा में हाल ही कुछ कदम दोनों देशों द्वारा चिन्हित किये गये है। जिनमें दवाई उत्पादन के निरिक्षण में आपसी सहयोग तथा कृषि उत्पादों को एक से दूसरे देश भेजने के लिये जो कठोर मापदण्ड है, उनको व्यापारिक बनाना इसमें शामिल है। साथ ही अब दोनों पक्ष द्विपक्षी व्यापार और निवेश की बाधाऐं दूर करने, एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं की दोनों देशों के बाजारों में पहुँच को अधिक सुविधाजनक बनाने व व्यापार तथा निवेश के विनिमय को मजबूत बनाने के लिये दोनों देशों की स्थानीय सरकारों की

सहायता करने के लिये आवश्यक कदम उठाने को सहमत हो गये है। निश्चित तौर पर ये सब कदम 21वीं सदी में दोनों देशों की दशा एवं दिशाओं के निर्धारक हैं।[5]

बहरहाल इतना तो माना जा सकता है जिसका एक उचित आधार भी उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आज भारत को चीन की और चीन को भारत की आवश्यकता हैं, दोनों एक साझा भाव से एक दूसरे के विकास में योगदान दे सकते हैं और ऐसा करके एशिया को समस्त विश्व के विकास का केन्द्र बना सकते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं रह गया है कि अब पश्चिमी निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाऐं जो पूँजीवादी उदार एवं कर्ज प्रधान रही है, का खोखला ढाँचा संसार के सामने आ गया है ऐसे में समस्त संसार की आशा का केन्द्र अब चीन-भारत जैसे बड़ी आबादी और बडे बाजारों वाले देश ही है। भारत और चीन चाहे तो व्यापार सन्तुलन के मुद्दे को हल कर एक दूसरे को लाभ पहुँचा कर 'बहुध्रुवीय विश्व निर्माण' और '21वीं सदी को एशिया की सदी' बना सकते है।

चीन दुनियाँ में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ दुनिया की सबसे बडी विदेशी मुद्रा कोष रखने वाली अर्थव्यवस्था और अघोषित रूप से तो दुनियां की सबसे बडी अर्थव्यवस्था हो चुकी है आज USA भी चीन के साथ व्यापार घाटे में फँसा हुआ है 100 अरब डॉलर से ज्यादा चीन का अमेरिका पर कर्जा है।[6] लेकिन भारत भी सबसे अधिक डेवलेपमेन्ट पोटेंशियल वाली अर्थव्यवस्था है भारत की 65 प्रतिशत आबादी युवा है जो उत्पादन में योगदान हेतु तैयार है खाद्यान्न में भारत आत्म निर्भर है और प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाऐं अपने में समेटे हुए है। चीन में बहुत तेजी से कल कारखाने और फैक्ट्रीया बनाई गई है परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय सीमाऐं उसके विकास के सामने बाधा है। चीन की एक बच्चा नीति से पहले का कामगार अब बूढ़ा हो चुका है और नई पीढ़ी एकलौते होने के कारण आराम पंसद (लालन-पालन में ज्यादा स्नेह होने से) है अत: अब चीनी तैयार माल को खपाने को भारत में निवेश करना चाहता है और भारत को निवेश की जरूरत है। IMF के इस अनुमान के बाद कि भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले समय में 7 से 8 प्रतिशत के बीच विकास दर हाँसिल करेगी। स्वाभाविक है चीन इन्वेस्टमेन्ट रिटर्नस को देखते हुए भारत में निवेश करने में अधिक दिलचस्पी लेगा। चीन वैसे भी मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट और रेल्वे प्रोजेक्ट मे निवेश को इच्छुक है चीन का बेड़ची फोटॉन मोटर कॉरपोरेशन पुणे में पांच अरब डॉलर का औद्योगिक पार्क बनाना चाहता है। ऐसा ही एक पार्क 18 अरब डॉलर की लागत से बड़ोदरा में भी बनाया जा रहा है। जो भारतीय दृष्टि से लाभदायक है।

भारत चीन के साथ एशिया ढाँचागत पूंजी निवेश बैंक (AIIB) में भी शामिल हो रहा है जिसका लाभ भारत को मिलेगा। इस प्रकार यह सहकार भाव दोनों को और अधिक नजदीक लाने का कार्य करेगा।[7]

पर्यटन और सांस्कृतिक दृष्टि से सहकार और सहयोग की संभावनाएँ दोनों देशों के बीच 1962 के युद्ध के परिणामस्वरूप आयी कटुता को हटाकर पीपुल टू पीपुल सम्पर्क कोन्टेक्ट में मदद करेगी और उसका आर्थिक फायदा भी दोनों देशों को होगा। पहले पर्यटन की बात करते हैं। भारत में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चीन से हमारे यहाँ सिर्फ 2 फीसदी लोग ही घूमने आते है। जबकि सम्भावना तकरीबन छह फीसद तक है। इसकी कई सकारात्मक वजह है। चीन में हाल के सालों में बड़े पैमाने पर सम्पन्नता आई है। चीन के लोगों में नई जीवन शैली के प्रति जबरदस्त आकर्षण है। हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा चीनी घूमने जाते है, पढ़ने जाते है या किसी कारोबार की वजह से बाहर जाते है लेकिन भारत में एक लाख चीनी भी नहीं आते है। जबकि वीजा ऑन अराइवल कर दिये जाने के बाद चार से पाँच लाख तक चीनी भारत घूमने आ सकते है। इस तरह चीन के साथ निकटता हमारे हित में होगी एक तो डायरेक्ट करेंसी भारत को मिलेगी दूसरा भारत घूमने आने वाले कुछ व्यापारी आदि अपने निवेश भारत में करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। शायद इसलिये दुनिया के आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते है कि हमें चीन को दोस्ताना संकेत देने मे जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए।[8] हाल के महिनों में इसी बात को ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय और खुद पी.एम. भी चीन को ई-वीजा सुविधा जारी रखने का पुरजोर समर्थन करते रहे हैं।

हालांकि यहाँ एक अन्य तथ्य यह भी है कि जिस देश को हम ई-वीजा और वीजा ऑन अराईवल जैसी सुविधायें प्रदान कर रहे है वह भारतीय नागरिको को नत्थी वीजा दे रहा है। इंटेलिजेन्स अधिकारियों ने पूर्व में चीन के नागरिकों द्वारा देश में जासूसी को लेकर भी अपनी चिंताऐं जाहिर की है लेकिन हमें इन बातों को किनारे करना ही होगा। हाँ यहाँ भारतीय आशा पर चीन तब खरा उतरता तो अच्छा रहता कि वह भी ऐसी ही एकतरफा घोषणा करता। सामान्यत: सर्तकता के चलते यह सुविधा आमतौर पर उन देशों को नहीं दी जाती जहॉ से घुसपैठ होने की आंशका हो या इसी प्रकार के दूसरे खतरों की आशंका हो। वास्तविकता यह है कि आज हमें चीन का निवेश चाहिए। सवाल यह है कि क्या चीन

को ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए तो आदर्श जवाब है हाँ लेकिन चीन को हमारी उतनी जरूरत नहीं है जितनी हमें चीन की है।

सांस्कृतिक दृष्टि से दोनों देश प्राचीन संस्कृतियों के धनी है दोनों की प्राचीन संस्कृतियों में व्यापार-वाणिज्य था, जिसका प्रमाण प्राचीन रेशम मार्ग माना जाता है साथ ही यह भी माना जाता है कि चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार भारत से हुआ है अत: दोनों सांस्कृतिक दृष्टि से भी साम्य रखने वाले देश है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चीन की यात्रा पर बौद्ध मठों का दौरा करना और भारतीय बुद्ध स्मारकों के सम्बन्ध में चर्चा करना बौद्ध धर्म को आधार बनाकर भारत-चीन के नागरिकों को पास-पास लाने का प्रयास कहा जाना चाहिए। बौद्ध स्थलों के पर्यटन एवं शैक्षणिक केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने का विचार भी वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी यात्रा पर नरेन्द्र मोदी का कहा गया वाक्य ''जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं हो सकता'' उनके इसी आशा और विश्वास को दृढ़ता प्रदान करता है।[9]

सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत की वैश्विक हस्ती को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। भारत की GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वोपरि है इससे भी यह बात प्रमाणित होती है। भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने विश्व भर में अपनी पैठ बना रखी है यहाँ तक कई देशों यथा ब्रिटेन आदि में तो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बडी डिमांड रहती है। भारत की इस ताकत या हुनर का समायोजन यदि चीन के हार्डवेयर या मशीनरी हुनर के साथ हो जाता है तो यह नि:सन्देह दोनों देशों के बीच एक बड़ी साझेदारी का सबब हो सकता है। चीनी हार्डवेयर टेक्नोलॉजी अपने आप में विश्व स्तरीय मानी जाती है दोनों यदि एक दूसरे की इस क्षमता का एक साथ मिलाकर उपयोग करे तो निश्चित तौर पर आई. टी. कम्प्यूटर और मोबाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एशिया में एक क्रान्ति ला सकते है और इस सन्दर्भ में जो वर्चस्व पश्चिम का है वह तोड़ा जा सकता है।[10]

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने अपना लोहा मनवा रखा हैं मंगलयान की सफलता के बाद अब चन्द्रयान की तैयारी भारत कर रहा है। अब तो भारत पेशेवर अंतरिक्ष प्रौद्योगिक देशों में शामिल हो चुका है, जो न केवल अपने प्रक्षेपास्त्रों को और सेटेलाइटों को प्रक्षेपित करता है बल्कि अन्य देशों के दूर संवेदी उपग्रहों को भी प्रक्षेपित कर पैसा कमा रहा है। चीन की भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऊँची उपलब्धियाँ हैं और वह इसी क्षेत्र में यदि भारत के साथ तकनीकी आदान-प्रदान करे तो इसमें दोनों देशों में अच्छी साझेदारी की उम्मीद जताई जा सकती है।

तकनीकी आदान प्रदान चीन लौह इस्पात आदि का बडा आयातक देश है और कच्चे माल का निर्यातक है भारत। हाँलाकि यह बात चीन के फायदे की नहीं होगी कि वह भारत को इस प्रकार की उच्च तकनीकी प्रदान करें जिससे वह अपने कच्चे माल को गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाकर निर्यात कर सके और मुनाफा कमाकर अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाये। लेकिन चीन को यह भली भाँति ज्ञान होना चाहिए कि भारत के साथ इन्हीं क्षेत्रों में उसे आदान-प्रदान कर उसे पश्चिमी खेमें में खासकर अमेरिका जापान, द. कोरिया, आस्ट्रेलिया आदि देशों की तरफ जाने से रोका जा सकता हैं। भारत को यदि बुलेट ट्रेन की तकनीक चीन नहीं प्रदान करता है तो वह जापान से ले लेगा तब चीन का नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि भारत-जापान सम्बन्ध चीन के लिये केवल आर्थिक नुकसान वाले ही न होकर सामरिक दृष्टि से भी अच्छे नहीं रहेंगे। यदि दोनों देश यह मानते और चाहते है कि एशिया को एक अलग दर्जा दिलाया जाये तो उसे भारत के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य करना ही होगा तभी भारत का 'मेड इन इंडिया' और 'स्किल्ड इंडिया' का सपना भी साकार होगा और एक-दूसरे के साथ साझेदारी तथा विश्वास के नये रास्ते खुलेंगें। शी जिनपिंग के शब्दो में ''एक दोस्ताना व अच्छे पड़ौस को विकसित करने का सपना'' साकार हो पायेगा। जिस प्रकार चीन की पकड़ पूरे एशिया पर होती जा रही है, उसे चाहिए वह सम्पूर्ण एशिया को विकसित करे।[11] यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि हम यह जान ले कि चीन ने 2003 से 2012 के बीच बांग्लादेश, भूटान, मालद्वीप, नेपाल, श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान को होने वाला अपना निर्यात दोगुने से अधिक कर लिया है और वर्तमान मे चीन, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे घनी आबादी वाले दक्षिण एशियाई देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अब चीन और भारत को खासकर चीन को चाहिए कि वह एशिया को अन्य देशों द्वारा तकनीक हस्तांतरित कर उनमें हस्तक्षेप करने से रोकने के लिये अपनी उच्च तकनीक को इनके साथ शेयर करे। जिससे समानता के साथ किया गया विकास ज्यादा स्थिर रह सके। देखा जाये तो जिस प्रकार और जिस सहयोगात्मक भाव के साथ सार्क सेटेलाइट नेविगेशन कार्यक्रम के पद्चिन्ह का विस्तार भारत कर रहा है उसी भाव को रखकर चीन भी अपनी तकनीक का हस्तांतरण या आदान-प्रदान भारत व अन्य देशों के साथ कर साझेदारी विकसित कर सकता है।[12]

जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को एशिया मे नियन्त्रण में करने और एशिया के विकासशील देशों को इसके दुष्प्रभावों से बचाने के लिये और इस सम्बन्ध में कार्बन उत्सर्जन के विकसित देशों के मनमाने मानदण्डों का विरोध करने के लिये भारत और चीन को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा भाव से कार्य करना चाहिए। पर्यावरण विद्रोह के एक समूह ग्रीन पीस ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते 2040 तक जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 200 मिलियन लोगों को दरबदर होना पड़ेगा और इसमें ज्यादातर गरीब देशों के लोग ही चपेट मे आयेंगे। यानि इसका खामियाजा भी विकासशील देशों को ही भुगतना पड़ेगा। ऐसे मे हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण एशिया या सम्पूर्ण एशिया के कुछ देशों को छोड़कर लगभग सभी की हालत अभी विकासशील और अल्प विकसित की स्थिति वाली ही है। जलवायु परिवर्तन के मामले में चीन और भारत पर भी विकसित देशों का दबाव लगातार बना हुआ है और वे क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और बाली रोडमेप के जरिये इन देशों पर कार्बन उत्सर्जन के लिये बराबर दबाव बनाये हुए है।[13]

इस में कोई दो राय नहीं हो सकती कि विकास की अंधाधुंध दौड़ में पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति इन्हीं विकसित देशों ने पहुँचाई है जो आज कार्बन कटौती के लिये विकासशील और अल्प विकसित देशों पर मनमानी शर्तें थोप रहे है। चूँकि वे अपना विकास कर चुके है और अपने उच्च स्तरीय व विलासिता प्रधान जीवन शैली को त्यागना नहीं चाहते। अत: स्वयं तो अपने उस स्तर में कटौती के लिये जो विकासशील देशों की अपेक्षा ज्यादा होनी चाहिए तैयार नहीं होते है एवं इन देशों पर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर कार्बन रेटिंग जैसे नये-नये पैमाने बनाकर इनकी विकासधारा को अवरूद्ध करना चाहते है। सनद रहे विकसित देशों का मुकाबला कभी भी दक्षिण एशिया के छोटे देश नहीं कर पायेगे अत: इस बाबत भी चीन-भारत को ही आगे आना पड़ेगा। ताकि एक खुशहाल पड़ौस और विकसित एशिया का निर्माण किया जा सके।[14]

जहाँ तक वैश्विक आतंकवाद का सवाल है दोनों देश एक स्वर में आतंकवाद का विरोध करते है। अनेकों बार अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और गोष्ठियों से दोनों ने एक स्वर में आतंकवाद का विरोध किया है, इसे मानवता व विश्व शांति के खिलाफ बताया है। आंतरिक आतंकवादी और अलगाववादी तत्वों से भी दोनों देश समान रूप से पीड़ित रहें हैं। चीन में उईगुर मुस्लिम समुदाय इसी प्रकार के आन्तरिक आतंकवाद का उदाहरण है। भारत में दोनों तरह का आंतकवाद रहा है वह चाहे भारत के पड़ौस द्वारा प्रायोजित रहा हो, चाहे वह आंतरिक अलगाववादी। भारत को अनेक बार इसी प्रकार के आतंक से दो-चार होना पड़ता रहा है। अलकायदा, लश्कर-ए-तौयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, सिमी इसी प्रकार के इस्लामिक आतंकवाद के उदाहरण है। आंतरिक आतंकवादी तत्वों में खालिस्तान, नक्सलवादी, लिट्टे, नागा अलगाववादी संगठन आदि प्रमुखता से लिये जाने जा सकते है।

चीन स्वयं अपने उस 46 अरब डालर के औद्योगिक कॉरिडोर जिसकी हाल ही में शी जिनजिंग द्वारा घोषणा की गई है सुरक्षा को लेकर चिंतित है। यह कॉरिडोर न केवल पीओके अपितु पाक के आतंकवाद प्रभावित बलुचिस्तान जिले से होकर निकलेगा। इसमें भी अब कोई सन्देह नहीं रह गया है कि चीन की मुस्लिम बहुल आबादी वाला हिस्सा जहाँ उईगुर में आतंकवाद आग की तरह फैल रहा है और चीन के लिये सिर दर्द बनता जा रहा है। वह इनके खिलाफ तिब्बत जैसी सख्ती से पेश नहीं आ सकता है। क्योंकि इससे चीन के पश्चिमी सीमा पर स्थित सभी मुस्लिम देशों की सहानुभूमि उनके प्रति होगी जिसका परिणाम चीन के लिये और ज्यादा घातक हो सकता है।[15]

निष्कर्ष

इस प्रकार हम इतनी संभावनाएँ व्यक्त करने की स्थिति में होते हैं कि उक्त क्षेत्रों में भारत-चीन के सम्बन्ध एवं इनकी आपसी अन्तनिर्भरता निरन्तर बढ़ती चली जायेगी। आपसी व्यापार वाणिज्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि इसका अकाट्य प्रमाण है एक-दूसरे के साथ आपसी हित साझा करते हुए एवं विभिन्न विवादों को पीछे छोड़ यह साझेदारी निरन्तर बढ़ती जा रही है जो 2015 तक 100 बिलियन डॉलर के आसपास है। नि:सन्देह यह आशातीत वृद्धि कही जा सकती है। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग की जरूरत कब पड़ जाये यह निश्चित नहीं है क्योंकि दोनों बड़े देशों की अरबों की आबादियों को खाद्यान्न किसी आपदा या अकालादि की स्थिति में भी तो चाहिए अत: इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय दृष्टिकोण से समृद्ध होते चीन से भारत में अधिकाधिक चीनी पर्यटकों का आगमन होना चाहिए। दोनों की समृद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का उपयोग दोनों आपसी पर्यटन को बढ़ाकर कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिरक्षा आदान-प्रदान एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी सहकार को बलवती बनाया जा सकता है। भारत आज न केवल खुद के उपग्रहों को सफलता से प्रक्षेपित कर रहा है बल्कि अब वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को व्यापार की तरह उपयोग कर धनार्जन कर रहा है ऐसे में दोनों देशों के बीच एक बड़े सहयोग का क्षेत्र यह

भी हो सकता है। आतंकवाद से मुकाबला चीन और भारत दोनों को मिलकर करना चाहिए। क्योंकि वह दिन दूर नहीं माना जा रहा जब हंटिंगटन की 'सभ्यताओं के टकराव' की भविष्यवाणी सही सिद्ध हो जायेगी। ऐसा ISIS के उभरने फैलने से भी समुचित सा जान पड़ता है। चीन ऊइगुर में आतंकवाद से पीड़ित है तो भारत काश्मीर में इसलिए दोनों को आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मोर्चा खोलना चाहिए। इसी प्रकार एशिया को वैश्विक क्षितिज पर सर्वोच्च पद पर लाने के लिए चीन और भारत को आपसी वर्चस्व की लड़ाई छोड़कर आपसी साझा भाव से मिलकर काम करना पड़ेगा। पूरे एशिया को एक देश अपने नियंत्रण या प्रभाव में रखे उससे ज्यादा इस महाद्वीप के हित की बात यह है, कि इस संदर्भ में भारत और चीन दोनों मिलकर काम करें।

उक्त के अलावा पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर के क्षेत्र में सहयोग, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक जैसे वैश्विक आर्थिक संगठनों में हित साझा करने, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, एशिया में बाहरी हस्तक्षेप को रोककर शांति बनाये रखने व विकसित देशों के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के क्षेत्र में दोनों देश साझा भाव रखकर कार्य कर सकते हैं। तभी 21वीं सदी एशिया की सदी साबित हो पायेगी।

सन्दर्भ सूची

1. पंत, पुष्पेश, 21वीं सदी में अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, टी.एम.एच. प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010
2. दृष्टिकोण मंथन, 16-30 जून, 2015, पृ. 27, सम्पादकीय, साभार हिन्दूस्तान
3. दृष्टिकोण मंथन, 16-30 जून 2015, पृ. 27
4. राष्ट्रदूत, 12 जुलाई, 2015, जयपुर
5. राष्ट्रदूत, 15 मई, 2015, नई दिल्ली
6. अभिव्यक्ति, सिविल सविर्सेज टाइम्स, मई 2015, अंक-2, नई दिल्ली
7. http://dipp.nik.in/toli-statistics/india-fdi aprial 2011
8. sg@expressindia.com, नवम्बर, 2006
9. रहीस सिंह, सम्पादकीय लेख, डेली न्यूज, 27 जून, 2015, जयपुर, पृ. 5
10. वेद प्रताप वैदिक, dr.vadik@gmil.com, 16 मई, 2015
11. अभिव्यक्ति, सिविल सर्विसेज टाईम्स, मई 2015, अंक-1, पृ. 7
12. वाजपेयी, अटल बिहारी, इण्डिया एण्ड चाईना चैलेन्जेज एण्ड अपोरचूनिटिज इन आई टी सैक्टर, चीन यात्रा के दौरान भाषण, स्ट्रेटेजिक डाइजेस्ट, जुलाई, 2003
13. चिनॉय, के.एम., रशिया-इण्डिया-चाइना : री-विजनिंग इन्टरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम, वर्ल्ड फोकस, अप्रेल, 2005 पी. 16
14. www.unep.org/cpi/briets/2007jan20doc?
15. जैन, बी.एम., अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, पाँचवाँ संस्करण 2013